G-7 शिखर सम्मेलन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

29 अगस्त, 2019

"G-7 शिखर सम्मेलन में सब कुछ सही नहीं था, लेकिन पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रम्प का सहयोग मिला।"

फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किये गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन जैसे जुड़वां मिशन पर दुनिया की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को संबोधित करना था, लेकिन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनकी बैठक थी। इस बार श्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर के बारे में उठ रहे सवालों को खत्म करने का बीड़ा उठाया।

श्री ट्रम्प द्वारा कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बारे में बार-बार दोहराये जाने और साथ ही पिछले हफ्ते एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी द्वारा यह कहना कि श्री ट्रम्प "प्रधानमंत्री मोदी से यह सुनना चाहते हैं कि कश्मीर में क्षेत्रीय तनाव को कम करने और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए वे क्या कर रहे हैं, के बाद श्री मोदी द्वारा इन सब सवालों का जवाब देना अनिवार्य हो गया था।

देखा जाये, तो अमेरिका के दोनों बयान भारत के इस बयान के विरोधी प्रतीत होते हैं जहाँ इसने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेना भारत के संविधान के तहत है तथा उनका यह 'आंतरिक मामला' है और कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से हल किया जाएगा।

हालांकि, इस आयोजन में भी श्री मोदी ने अपने इस संदेश को घर-घर तक पहुंचाया और श्री ट्रम्प ने भारत के इन दोनों बयानों से दूरी बना ली। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए दिलचस्पी दिखाई और फैसला किया है कि उनके व्यापार प्रतिनिधि, यूएसटीआर रॉबर्ट लाइटहाइजर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सितंबर में मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले मिलेंगे।

श्री मोदी और श्री ट्रम्प के बीच की बातचीत इस साल जी-7 शिखर सम्मेलन की विशेषता वाले व्यापक विषयों के अनुरूप प्रतीत हुई, जहाँ द्विपक्षीय बैठकें बहुपक्षीय बैठक की तुलना में थोड़ी अधिक सफल रहीं। मेजबान के रूप में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन अन्य जी-7 सदस्यों ने जेसीपीओए परमाणु समझौते के भविष्य पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने सम्मेलन में शामिल करने के किसी भी सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

श्री ट्रम्प ने रूस को वापस क्लब में आमंत्रित करने के लिए जोर दिया। विदित हो कि 1998 में रूस के शामिल होने के बाद समूह जी-8 के रूप में जाना गया (जो दुनिया के आधे से अधिक धन का प्रतिनिधित्व करता है), लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे समूह से निकाल दिया गया।

विभिन्न सत्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित नौ विशेष अतिथियों में से एक के रूप में, श्री मोदी ने कहा कि भारत किस तरह से अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को निभा रहा है, लेकिन यह एक सत्र था जहाँ श्री ट्रम्प, जिनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी, ने पेरिस समझौते से वॉकआउट किया था और यहाँ भी अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई।

जी-7 के सदस्यों ने अमेजन के जंगलों में लगी आग के संकट पर भी चर्चा की और ब्राजील को 20 मिलियन डॉलर से अधिक धन देने की पेशकश की, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और श्री मैक्रॉन के बीच एक विवाद के बाद यह विफल हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शिखर सम्मेलन समाप्त होने के साथ ही, समूह के 44-वर्षीय इतिहास में पहली बार, कोई संयुक्त संवाद नहीं हुआ।

GS World टीम...

G-7 समूह

चर्चा में क्यों?

- दुनिया की सात सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थवओं के समूह जी-7 का शिखर सम्मेलन (24 से 26 अगस्त तक) फ्रांस के बिरिट्ज शहर में आयोजित किया जा रहा है।
- यह जी-7 समूह के देशों का 45वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें दुनिया की कई महाशक्तियां शिरकत कर रही हैं।
- हालांकि, भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है।
- इस सम्मेलन का एजेंडा आय और लैंगिक असमानता से लड़ने और जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित है।

क्या है?

- जी-7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थीओं का समूह है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अमेरिका इसके सदस्य हैं। इसे ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) यानी जी-7 कहा जाता है।
- औद्योगिक रूप में विकसित देशों का यह समूह खुद को 'कम्यूनिटी ऑफ वैल्यूज' यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय कहता है।
- मानवाधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, आर्थिक समृद्धि व निरंतर विकास इसके मुख्य सिद्धांत हैं।
- दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल व रफ्तार को निर्देशित करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
- दुनिया की कुल आबादी का जहाँ 10वां हिस्सा इन देशों में है, वहीं वैश्विक जीडीपी में इन देशों की 40 प्रतिशत भागीदारी है।

समूह का काम

- शुरुआत में यह छह देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था।
- अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह जी-7 बन गया। जी-7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं।
- प्रत्येक सदस्य देश बारी-बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है।
- यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआईवी-एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं, जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थीं।
- शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

पहले जी-8 था नाम, रूस हुआ बाहर तो बना जी-7

- इस समूह का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था और तब इसमें केवल 6 सदस्य थे और इसे जी-6 के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद

इसमें 7 सदस्य हो गए, जिसके बाद इसे जी-7 नाम दिया गया।

- 1998 में रूस भी इसमें शामिल हुआ, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के कारण 2014 में इसे समूह से निकाल दिया गया, जिसके बाद यह फिर से जी-7 के रूप में जाना जाने लगा।
- अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें रूस को शामिल करने पर जोर दिया है।

कितना प्रभावी है?

- जी-7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है।
- समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है।
- समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका है।

भारत, चीन जी-7 का हिस्सा क्यों नहीं हैं?

- भारत के साथ-साथ चीन भी जी-7 देशों का हिस्सा नहीं है, जबकि इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है।
- इसकी एक बड़ी वजह यहाँ की बड़ी आबादी और प्रति व्यक्ति आय में कमी है। जी-7 समूह के देशों के मुकाबले इन दोनों देशों में न केवल जनसंख्या कई गुना ज्यादा है, बल्कि यहां प्रति व्यक्ति आय भी उनके मुकाबले काफी कम है।
- ऐसे में इन दोनों देशों को विकसित अर्थव्यंवस्था नहीं माना जाता और इसलिए ये इस समूह का हिस्सा नहीं हैं।

पीएम मोदी को जी-7 में क्यों मिला न्यौता?

- भारत हालांकि जी-7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इस बार जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया गया है।
- पीएम मोदी को यह खास आमंत्रण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ओर से मिला है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जी-7 के लिए पीएम मोदी को मिला यह आमंत्रण वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती धाक को दर्शाता है।
- यह भारत और फ्रांस की बढ़ती नजदीकियों को भी दर्शाता है। फ्रांस पहुंचने पर पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ था, उस दौरान भी मैक्रों के साथ उनके गर्मजोशीपूर्ण रिश्ते देखने को मिले थे।
- भारत के साथ-साथ इस बार ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और रवांडा जैसे देशों को भी जी-7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

प्रमुख चुनौतियां

- आंतरिक रूप से जी-7 में कई असहमतियां हैं। पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और आयात करों को लेकर अन्य सदस्यों के साथ भिड़ गए थे।
- अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से कोई जी-7 सदस्य नहीं है। अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से उभरते ब्राजील और भारत भी इसका हिस्सा नहीं हैं।
- कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक जी-7 राष्ट्रों में से कुछ को पीछे छोड़ देंगी।

Comm

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- **G-7 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

1. अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी महाद्वीप से कोई भी देश इस समूह का सदस्य नहीं है।
2. इसके शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।
3. इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding G-7.**

1. No countries from Africa and Latin American continent are members of this group.
2. Representatives of other countries and international organizations are also invited in this summit.
3. It's first summit was held in 1975.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Only 3

(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में G-7 की बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया। इस बैठक में बहुपक्षीय की तुलना में द्विपक्षीय मुद्दों पर अधिक बल दिया गया। भारत व अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, भारत के लिए क्यों अहम है? चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Recently, the G -7 meeting was held in France. In this meeting more emphasis was placed on bilateral issues than on multilateral. Why is the bilateral meeting between India and America important for India? Discuss **(250Words)**

नोट : 28 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।